Fax Message No. 5272 /ICAR HQ
Dated 5/7/2011
No of Pages 05

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAVAN : NEW DELHI

F.No. 9(7)/2001-CDN(A&A) Dated the 4th July, 2011

ENDORSEMENT

A copy of the following Office Memoranda issued by Ministry of Finance, Department of Expenditure are posted on the ICAR Web-Site www.icar.org.in for information, guidance and necessary action :

i) O.M. No. 2(13)/2008-E.II(B) dated 4th March, 2011 - Decision of the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to re-classification of cities/towns for grant of House Rent Allowance (HRA).

ii) O.M. No. 2(14)/2010-E.II(B) dated 15th June, 2011 Re-classification of Saharanpur as "Y" class city for the purpose of House Rent Allowance.

(Sanjeevan Prakash)
Sr. Finance & Accounts Officer

Distribution :

I ICAR Research Institutes etc :

1. The Directors/Joint Directors/Project Directors of all Research Institutes/Project Directorates/National Research Centres and Bureaux.
2. Project Coordinators/Coordinated Research Projects/Zonal Coordinators.
3. The Finance & Accounts Officers of all Research Institutes, Project Directorates, National Research Centres and Bureaux.

II ICAR Headquarters :

1. All Officers/Sections, ICAR, Krishi Bhavan, New Delhi including Krishi Anusandhan Bhavan I & II, NASC, Pusa, New Delhi.
2. ADG(CDN)/ADG(PIM)/PD, DKMA
3. Director(A)/DS(GAC)
4. Sr. PPS to Secretary, DARE & DG, ICAR/PPS to Additional Secretary, DARE & Secretary, ICAR/PS to AS&FA, DARE/ICAR
5. Sh. Hans Raj, Information System Officer, DKMA, KAB-I for placing the above Office Memoranda on ICAR Web-site.
6. Secretary (Staff Side), IJSC, Krishi Bhavan, New Delhi.
7. Guard file.
8. Spare copies (10).

No. 2(13)/2008 E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

New Delhi, 4th March, 2011.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Decision of the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to re-classification of cities/towns for grant of House Rent Allowance (HRA).

The undersigned is directed to refer to para 6 of this Ministry's O.M. of even number dated 29.08.2008 on the above mentioned subject, vide which the special dispensation for grant of HRA has been allowed to continue to (i) Faridabad, Ghaziabad, Noida & Gurgaon at "X" class city rates and (ii) Jalandhar Cantt., Shillong, Goa & Port Blair at "Y" class city rates and to state that the special dispensation allowed to Panchkula for grant of HRA at par with Chandigarh vide this Ministry's O.M. No.2(2)/2001-E.II(B) dated 16.06.2003, shall also continue.

2. In this context, it is also clarified that any other similar special dispensation allowed by this Ministry in the past in respect of other cities for grant of HRA at higher rates and not specifically mentioned in this Ministry's O.M. of even number dated 29.08.2008, shall continue to apply, if the same has not been superceded/dispensed with or the existing classification of such city has not been revised to a higher classification on account of the population criteria, vide O.M. dated 29.08.2008.

3. These orders shall be effective from 1st September, 2008.

4. All other conditions governing grant of HRA under existing orders shall continue to apply.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

6. Hindi version is attached.

(Anil Sharma)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to C&AG and U.P.S.C., etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

स.2(13)/2008-ई.II (वी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली 04 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए शहरों/कस्बों के पुनर्वर्गीकरण के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 29.08.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. के पैरा 6 जिसके तहत (i) फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोयडा और गुड़गांव के लिए "एक्स" श्रेणी के शहरों की दरों पर और (ii) जालंधर छावनी, शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर के लिए "वाई" श्रेणी के शहरों की दरों पर मकान किराया भत्ता का विशेष भुगतान जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है, के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के दिनांक 16.06.2003 के का.ज्ञा. सं. 2(2)/2001- ई II (वी) के तहत पंचकुला के लिए चंडीगढ़ के बराबर मकान किराया भत्ते की विशेष अनुमति भी जारी रहेगी।

2. इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्य शहरों के संबंध में उच्चतर दरों पर मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए विगत में इस मंत्रालय द्वारा अनुमत किसी अन्य समान प्रकार की विशेष अनुमति जिनका दिनांक 29.08.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जारी रहेंगी, यदि उसका अधिक्रमण नहीं किया गया है/समाप्त नहीं किया गया है अथवा दिनांक 29.08.2008 के का.ज्ञा. के तहत जनसंख्या मापदंड के कारण ऐसे शहर के विद्यमान वर्गीकरण को उच्चतर वर्गीकरण में संशोधित नहीं किया गया है।

3. ये आदेश 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे।

4. विद्यमान आदेशों के तहत मकान किराया भत्ता को संशोधित करने वाली अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अ॰ शर्मा

(अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार सी एण्ड एजी और यूपीएससी आदि को प्रति (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

No. 2(14)/2010-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

New Delhi, 15th June, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Re-classification of Saharanpur as "Y" class city for the purpose of House Rent Allowance – regarding

The undersigned is directed to invite attention to this Ministry's O.M No.2(21)/E.II(B)/2004 dated 18.11.2004 & O.M. No.2(13)/2008-E.II(B) dated 29.08.2008 regarding re-classification of cities on the basis of the population figures of 2001 census for the purpose of HRA to the Central Government employees and to say that the Government of Uttar Pradesh vide their Notification No.2176/9-7-09-53J/1998 dated 01.10.2009 reconstituted the area of Saharanpur (M.B.) by adding certain areas within its Municipal limits and re-named it as Saharanpur Municipal Corporation, which resulted in an increase in population of 'Saharanpur Municipal Corporation' to qualify it for classification as 'Y' class city for the purpose of House Rent Allowance to the Central Government employees.

2. The President is, accordingly, pleased to decide that Saharanpur city (within its Municipal limits) shall stand re-classified as "Y" class city for the purpose of grant of House Rent Allowance to the Central Government employees posted there.

3. These orders shall be effective from **1st June, 2011**.

4. The orders will apply to all civilian employees of the Central Government. The orders will also be applicable to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

(Anil Sharma)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to C&AG and U.P.S.C. etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

संख्या 2(14)/2010-संस्था.II(ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
•••

नई दिल्ली, 15 जून, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ सहारनपुर का "वाई" श्रेणी में पुनर्वर्गीकरण ।**

अधोहस्ताक्षरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर शहरों के पुनर्वर्गीकरण के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं. 2(21)/संस्था-II(ख)/2004 एवं दिनांक 29.08.2008 के का.ज्ञा. सं. 2(13)/2008-संस्था-II(ख) की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 01 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना सं. 2176/9-7-09-53-जे/1998 द्वारा सहारनपुर (एम.बी.) क्षेत्र में कतिपय क्षेत्रों को जोड़कर इसकी नगरपालिका सीमाओं को पुनर्निर्धारित कर दिया और इसका पुनः नामकरण सहारनपुर नगर निगम के रूप में कर दिया जिसके परिणामस्वरूप, 'सहारनपुर नगर निगम' क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ गई और इस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ इसने "वाई" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकरण हेतु अहर्ता प्राप्त कर ली है।

2. तदनुसार, राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि यहाँ तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ सहारनपुर (नगर निगम सीमा के अंतर्गत) "वाई" श्रेणी के शहर के रूप में पुनर्वर्गीकृत माना जाएगा।

3. ये आदेश 01 जून, 2011 से प्रभावी होंगे।

4. ये आदेश केंद्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान किया जाता है। सशस्त्र बल के कार्मिकों एवं रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अ. शर्मा
(अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि ।

प्रति: मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य अतिरिक्त प्रतियों के साथ) ।